संसद में बहस

''गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2008''

**The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2008**

# सरकार जागी, पर देर से

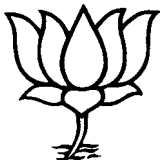

Hkkjrh; turk ikVhZ

## प्रकाशकीय

आतंकवाद भारत की प्रमुख समस्या हैं। भाजपा के नेतृत्ववाली राजग सरकार ने आतंकवाद को जड़ समेत खतम करने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनी 'पोटा' लागू किया था लेकिन संप्रग सरकार ने सत्तासीन होते ही सबसे पहले पोटा कानून को वापस ले लिया, जिसके चलते आतंकवादियों का दुस्साहस बढ़ता गया। आतंकवाद के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर भारी जनदबाव पड़ा और अंततः उसने संसद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक-2008 तथा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक-2008 प्रस्तुत किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं भाजपा सांसद श्री खालबेल स्वाईं ने दोनों विधेयकों का सिद्धांततः समर्थन करते हुए कहा कि संप्रग सरकार ने पोटा कानून का विरोध करने की अपनी आठ दस वर्ष पुरानी गलती सुधार ली है लेकिन इस दौरान देश की जनता को आतंकवादियों के हाथों जान-माल की भारी तबाही का सामना करना पड़ा। राज्यसभा में भाजपा सांसद श्री अरुण जेटली एवं श्री कलराज मिश्र ने बहस में हिस्सा लिया। श्री जेटली ने कहा कि इस नए विधेयक में पोटा के एक बड़े हिस्से को ही शामिल किया गया है और इसकी भाषा भी लगभग वैसी ही है।

हम इस पुस्तिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक-2008 तथा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक-2008 पर संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों के संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं।

**भारतीय जनता पार्टी**

दिसंबर, 2008

लोकसभा

# आतंकवाद के विरूद्ध पूरा विपक्ष सरकार के साथ

**लाल कृष्ण आडवाणी**

सभापति महोदय, इस बार का सत्र 10 दिसम्बर को शुरू हुआ। स्वाभाविक था कि 11 तारीख को सदन की कार्यवाही औपचारिक रूप से वास्तव में शुरू हुई, क्योंकि 10 तारीख को पूर्व प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित हो गया था। पहले दिन ही हमने मुम्बई की घटनाओं पर चर्चा की। पूरे सदन ने एक स्वर से सारी दुनिया को यह बताया कि जहां तक आतंकवाद की चिंता का सवाल है, यह सदन जो देश का प्रतिनिधि है, वह एक है। मैंने अपनी पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से जो कुछ कहा, उसे दोहराते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जहां तक इस आतंकवाद की चिंता का सवाल है, सरकार इस चिंता पर विजय पाने के लिए जो भी कदम उठाएगी, जो हमें सही लगते हैं, आवश्यक लगते हैं, तो मेरा दल और एनडीए उसका समर्थन करेंगे।

इसके कारण भी और आज जो दो विधेयक पेश किये गये हैं, जिनमें जो कमियां मुझे दिखाई देती हैं, उनका उल्लेख मैं करुंगा, लेकिन मैं आरम्भ में ही कहना चाहूंगा कि मैं सिद्धांतत: इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। अभी मैंने माननीय गृह मंत्री जी को यह कहते हुए सुना कि हमारा अगला सत्र फरवरी में होगा, मुझे लगा कि क्या यह सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होता कि जो अलग-अलग व्यू-पाइंटस हैं जिनका उल्लेख करके आपने यह बनाया है तथा सदन और देश के लिए अगर इस विधेयक को भी हम स्टेंडिंग कमेटी को भेजते, यह निर्देश देते हुए कि उनको फरवरी महीने से पहले सारी चर्चा और विचार-विमर्श, जिन-जिन लोगों से सलाह करनी है, उसको लेकर हमारे पास आयें। आपने स्वयं कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और हमने जो स्टेंडिंग कमेटीज बनाई हैं वे इस उद्देश्य से बनाई हैं कि महत्वपूर्ण



विधेयक स्टेंडिंग कमेटी के पास जाकर, ठीक प्रकार से उनके सब पहलुओं पर विचार करके और खासकर ऐसा विधेयक जिसमें शासन और प्रमुख विरोधी दल, दोनों सिद्धांतत: एकमत हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने इसके बारे में पहले आग्रह नहीं किया क्योंकि मुझे कभी-कभी संदेह होता था कि यह सत्र अंतिम सत्रन हो जाए। लेकिन जब ऑफिशियली आज कहा गया कि नहीं फरवरी के माह में हम फिर मिलेंगे तो मुझे लगा कि अच्छा होगा अगर अभी भी शासन इस पर विचार कर सके और इस पूरे सदन को आज हम चार या छह घंटे में इसे पारित कर लें, उसकी बजाए स्थायी समिति के पास जाए और जिसमें अलग-अलग लोगों से विचार भी ले लें, चूंकि इस पर सिद्धांतत: हम सहमत हैं। एनडीए और आप सहमत हैं, कुछ रिजर्वेशन्स हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरे जो रिजर्वेशन्स हैं मैं उनका उल्लेख करुंगा, वे इनएडीक्वेसीज के हैं, सिद्धांतत: आपत्ति नहीं है, न फैडरल एजेंसी पर और न ही आप जो एंटी टैरर कानून लाए हैं, उसके बारे में। लेकिन यह शासन का अधिकार है, शासन निर्णय करे, लेकिन मैं सुझाव के रूप में अपनी बात आपके सामने रखता हूं।

मुझे आज संतोष है और संतोष इस बात का है कि लगभग 10 साल तक जो स्टेंड सरकार ने लिया और जब विपक्ष में थे, तब भी उन्होंने वही स्टेंड लिया। यह आज की बात नहीं है। अचानक 10 साल के अंत में उन्होंने अपना स्टेंड मूलत: बदला है। मूलत: इस बात में बदला है कि जिस समय प्रीवेंशन ऑफ टैरेरिज्म एक्ट हम लाए थे, पहले आर्डिनेंस के रूप, फिर विधेयक के रूप में और जब विधेयक राज्य सभा में पास नहीं हुआ तो जाइंट सेशन के सामने, उस समय ऐसा नहीं है कि उस समय विपक्ष जो था वह आतंकवाद का मुकाबला करने के विरूद्ध था। नहीं, हम आतंकवाद को खत्म करने के पक्ष में थे और आप पक्ष में नहीं थे, यह अंतर नहीं, दोनों आतंकवाद को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन आपका मत था कि जो आज कानून है वह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है, जबकि हम इस मत के थे कि यह पर्याप्त नहीं है। हमने यह बात न केवल देश के भीतर कही बल्कि हमारे उस समय के प्रधान मंत्री जी ने अमरीका में भी जाकर वह बात अमरीका को 9/11 से भी पहले कही कि आप अगर समझते हैं कि आतंकवाद की जो विभीषिका है और उनको बताया कि हमें कितनी तकलीफ

हुई है और हमको तकलीफ इसलिए हुई है कि हमारे लिए आतंकवाद एक वार का सब्सीट्यूट हमारे पड़ोसी देश ने बना दिया।

अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी देश ने हमारे साथ तीन-तीन युद्ध किए। जब इन युद्धों में उसे सफलता नहीं मिली, तब उसने वर्ष 1971 के युद्ध के बाद, जब वहां सैनिक शासन हुआ, उसके बाद योजनापूर्वक प्रोक्सी वार की नीति आतंकवाद के माध्यम से अपनाई। इस प्रयोग में सबसे पहले पाकिस्तान ने पंजाब को चुना और फिर जम्मू-कश्मीर तथा फिर सारे देश में आतंकवाद फैलाया। अस्सी के दशक के शुरूआत से ही हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अमरीका में आतंकी हमला वर्ष 2001 में हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के सामने यह बात कही कि अमरीका यह न समझे कि वे चाहे विश्व के दूसरे देशों से दूर है, इसलिए शायद आतंकवाद से बचा रहेगा। 9/11 की घटना हुई और शायद आतंकवाद के इतिहास में इस प्रकार का भयंकर कांड कभी नहीं हुआ तथा भगवान न करे कि ऐसा कभी दोबारा हो। उस भयंकर कांड में आतंकवादियों ने चार हवाई जहाज हाईजैक करके उनका मिसाइल्स के रूप में प्रयोग किया। उसके कारण अमरीका हिला, दुनिया के दूसरे देश भी हिल गए। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 28 सितम्बर, 2001 को 1373 प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने दुनिया के सब देशों से कहा कि आतंकवाद भयंकर समस्या है और सामान्य अपराध के लिए जो कानून बने हुए हैं, वे उसके लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए आतंकवाद के लिए विशेष कानून बनाएंगे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके द्वारा प्रस्तुत बिल, अन लॉ फुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल, 2008 को देख कर आश्चर्य हुआ। वर्ष 2008 में आप अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) बिल के एक्ट के प्रिएम्बल को अमेंड कर रहे हैं। मुझे याद नहीं कि पहले कभी किसी ने प्रिएम्बल को अमेंड किया हो। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि वर्ष 2001 में जो सलाह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने दुनिया को दी और जिसका पालन दुनिया के प्रायः सभी देशों ने अमरीका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने आदि देशों ने किया। मेरा बहुत से देशों में जाना हुआ और सभी देशों ने कोई न कोई कानून बनाया और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान ने भी कानून बनाया था। हमने जब बनाया, उस



समय आप विपक्ष में थे और आपने इस प्रकार से हम पर हमला किया मानो हमने कोई अपराध कर दिया हो। हमने अगर प्रिवेंशन आफ टेरोरिज्म एक्ट बनाया, तो क्या हमने अपराध किया था। यह जो रेयर प्रावधान भारत के संविधान में है कि अगर लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के मत में अंतर हो तो निर्णय ज्वायंट सैशन बुलाकर किया जाएगा। भारत के इतिहास में ज्वायंट सैशन शायद दो बार या तीन बार बुलाया गया है। आज मैं देखता हूं कि अचानक सरकार को लगता है कि एक विशेष नए कानून की जरूरत है, जबकि पिछले आठ-दस साल इस कानून को बनाने की बात नहीं सोची। मैंने कहा कि मुझे संतोष है, लेकिन मैं खुशी प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं। आखिर एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कह सकते। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए और सुबह तथा शाम के समय के बीच में अनर्थ हो जाए, उस भूल के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, तो मैं उस व्यक्ति को भूला जरूर कहूंगा। आपने एक प्रकार से इस बिल को प्रस्तुत करके और उसकी वकालत करके तथा यह कह कर कि आज ही इसे पास करना है, एक प्रकार से आपने अपनी गलती स्वीकार की है और आपको करना भी चाहिए कि आप दस साल गलत थे। आपको गलती स्वीकार करनी भी चाहिए। स्वयं आपने अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल के क्लाज़-2 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी के बारे में लिखा है।

हमने नहीं किया था। हमने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पोटा पास किया था। आपने उसे मैंडेटिड माना। एक प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट है।

"Whereas the Security Council of the United Nations in its 4,385th meeting adopted Resolution No…so and so, etc., etc.,.. and whereas.. so and so…and whereas the Central Government in exercise of its powers conferred by section 2 of the United Nations Security Council Act has made the prevention and suppression of terrorism implementation of Security Council Resolution Order."

You have quoted all the Resolutions of the United Nations Security Council adopted in respect of terrorism. बहुत अच्छा किया

है। मैंने कहा कि मुझे इससे संतोष है लेकिन मैं कहूंगा जैसे कुम्भकरण को लंबी-लंबी नींद आती थी वैसे ही आप 7-8 साल की नींद के बाद जगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार करते कि इस बात में गलत थे। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था जिस की कटिंग मुझे किसी ने दी है। "This is old wine in new bottle." "UPA has returned to POTA." These are the headings. आप चाहे कुछ भी इन्कार करें। मैं उस समय मानता था कि हम बिना स्पैशल कानून के टैररिज्म का सामना नहीं कर सकते थे। मैं नहीं जानता कि मेरे वामपंथी साथी इस पर क्या कहने वाले हैं। उन्हें भी समझना चाहिए। मुझे स्वयं अनुभव है कि आपके मुख्यमंत्री कई बार मुझे कहते थे कि जब तक इस मामले में देश कठोर नहीं होगा, तब तक समस्या बड़ी भयंकर रहेगी।

आजकल के अखबारों में छपेगा कि Left and BJP vote together. लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते।

Now I do not believe in political untouchability as you believe. I do not. आप अगर सही बात करेंगे तो मैं उसका समर्थन करूंगा। आप गलत बात करेंगे तो चाहे आप मेरे साथ होंगे तो भी मैं विरोध करूंगा।

यह बात बार-बार कही जाती है कि इसका इसलिए विरोध किया गया कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या कोई कानून बना है जिस का दुरुपयोग न हो सके। बहुत सारे साधारण कानून हैं जिनका बहुत दुरुपयोग होता है। इस बात को लॉ कमिशन ने बड़े प्रभावी रूप से लिखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट राजस्थान वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया को कोट किया है। The Mohely Commission had quoted that as part of a Law Commission Report. Law Commission's Report is there on Prevention of Terrorism Bill. जिस में उन्होंने कहा है

"It must be remembered that nearly because power may sometimes be abused, it is not ground for denying the existence of power. The wisdom of man has not yet been able to conceive of a Government with power sufficient to answer all the legitimate needs and at the same time incapable of mischief.

मतलब लैजिटिमेट नीड है कि टैररिज्म पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कोई ऐसी सरकार नहीं है और इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कि सरकार



को उसके खिलाफ अधिकार भी दे और साथ-साथ उसका दुरुपयोग न हो सके, इसका भी प्रबंध करे। सेफगार्ड प्रोवाइड करने चाहिए। जब हमने प्रिवेंशन ऑफ टेरेरिज्म एक्ट बनाया था तब मैंने अपने सब अधिकारियों को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में टाडा के बारे में जो आपत्तियां की गई हैं कि इस तरह से दुरुपयोग हो सकता है इसलिए सेफगार्ड इनकारपोरेट करो और वो किए गए क्योंकि यह टेरेरिज्म और डिसरप्टिव एक्टिविटी के खिलाफ था। आपने भी कुछ किए हैं, बहुत अच्छा किया है। मैं इससे इंकार नहीं करूंगा लेकिन बेसिकली यह सोचना कि क्योंकि किसी लॉ का दुरुपयोग हो सकता है इसलिए यह पास नहीं होना चाहिए, यह सरासर गलत है। आज आपने यह बिल लाकर स्वीकार किया है कि हां, हमसे यह गलती हुई है लेकिन कहने के लिए तैयार नहीं हैं। हिन्दुस्तान में टेरेरिज्म पर विजय प्राप्त करने के लिए स्पेशल लॉ जरूरी है। लेकिन स्पेशल लॉ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, देखना होगा। आप जो बिल लाए हैं मैं उसमें इनएडीक्वेसिस और मेरी दृष्टि में जो होना चाहिए, बताऊंगा। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा पुलिस अफसर के सामने कोई कन्फेशन हो तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह एडमिसिबल नहीं है क्योंकि स्वीकार तो होगा नहीं। कोई अपराधी स्वयं कन्फेस करता है और कहता है कि मैंने मर्डर किया है, It is not conclusive evidence. यह कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसके साथ कोरोबोरेटिव एविडेंस कितना है। यह भी अधिकार है कि कोई कहे कि मैं कन्फेस करता हूं तो रिट्रेक्ट करने का भी अधिकार है। वह कोर्ट के सामने कहे कि मैं रिट्रेक्ट करता हूं। आप स्वयं वकील हैं और आप यही सब बातें ज्यादा जानते हैं। मैंने वकालत पढ़ी तो है लेकिन कभी प्रेक्टिस नहीं की लेकिन इतना मैं जानता हूं कि पुलिस अफसर के सामने कन्फेशन को क्यों एडमिसिबल एविडेंस किया। अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया है, क्या उसके लिए और एविडेंस लाएंगे? उसकी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगी क्योंकि पुलिस अफसर या ज्यूडिशिएल अफसर या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया गया है? हां, यह प्रेस्क्राइब करना चाहिए कि इस लैवल का पुलिस अफसर होना चाहिए जिसके सामने हो तो वह एडमिसिबल एविडेंस होगी, it does not become conclusive evidence. यह कन्क्रीट केस है जो अभी आया है कि एक आतंकवादी पकड़ा गया। तुका राम ने

बहादुरी की और उसे पकड़ा। वह सब कुछ बताने के लिए तैयार होगा तो भी साधारण लॉ के तहत एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। इसलिए मैं लॉ कमीशन की ऑब्जर्वेशन कोट करना चाहूंगा। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं जिसमें 73 रिपोर्ट में कहा है।

Mr. Home Minister, I am sure you have read it. But even then I would like to draw your attention to it.

"The act of terrorism by its very nature generates terror and a psychosis of fear among the populace. It is difficult to get any witnesses because people are afraid of their own safety and safety of their families. It is well known that during the worst days in Punjab even the judges and prosecutors were gripped with such fear and terror that they were not prepared either to try or to prosecute the cases against the terrorists. That is also stated to be the position today in Jammu and Kashmir and this is one reason which is contributing to the enormous delay in going on with the trials against the terrorists. In such a situation, insisting upon independent evidence or applying the normal peacetime standards of criminal prosecution may be impractical."

These provisions have been included in most laws prepared all over the world to deal with terrorists. यह सोचना कि यह लॉ इतना स्ट्रिंजेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि माइनोरिटी इसके खिलाफ है। आप इस प्रकार से कह कर माइनोरिटी को बदनाम कर रहे हैं। This is a law against terror; this is a law against terrorists that we enacted and which you are also enacting today.

You cannot now claim कि वह जो था, वह कम्युनल लॉ था और यह सेक्युलर लॉ है, यह तो नहीं कहोगे, उम्मीद करता हूं। आपने देश का बहुत नुकसान किया है by trying to see laws against terror through the prism of majority and minority. I said it that day and I repeat it today. मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हिंदुस्तान में यहां की कांस्टिटुंट असैम्बली, जो उस समय अपने संविधान पर विचार करने बैठी, जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था। यह विभाजन कांग्रेस नहीं चाहती थी, देश नहीं चाहता था और वह विभाजन इस आधार पर हुआ कि कहां हिन्दू बहुमत है और कहां मुसलमान बहुमत है और उन परिस्थितियों में पाकिस्तान ने अपने को



थियोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर किया। हिन्दुस्तान ने अगर सेक्युलरवाद अपनाया तो यह स्वयं में एक ऐसी बात है कि जिसे दुनिया का कोई देश भूल नहीं सकता और हिन्दुस्तान भी नहीं भूल सकता और बहुत उचित किया, उसके आधार पर हमने साठ साल देश को चलाया। लेकिन फिर भी इतनी देर हर चीज को इस चश्मे से देखना, इससे न देश का भला है और न अल्पसंख्यकों का भला है। आप उनका भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इस चश्मे से मत देखो। इस चश्मे को एक तरफ रखकर इन्डिपैंडैन्टली देखो कि टैररिज्म का मुकाबला करने के लिए कैसे-कैसे कानून जरूरी हैं। साधारणत: कोई इंटरसैप्शन ऑफ मैसेज, टेलिफोन टॉक वह एडमिसिबल एविडैन्स नहीं है। हमने प्रावधान बनाये, जिसमें Interception of telephonic talks and messages coming from, say, abroad to here, to the terrorist concerned, that became an admissible evidence. दे सकते हैं, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री, जो ढेर सारे प्रावधान थे relating to interception of messages. उन्हें भी इस नये कानून में समाविष्ट करें। उसकी एडिमिसिबिलिटी को स्वीकार करें। उसमें प्रावधान था कि वह एडमिसिबल होगा, इंटरसैप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से कंफैशन रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर्स एडमिसिबल एविडैन्स होना चाहिए, वैसे एडमिसिबिलिटी ऑफ इंटरसैप्टिव इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि कानून का दुरुपयोग होता था, टाडा का भी दुरुपयोग होता था। मैं इनकार नहीं करूंगा और एक स्टेज पर मुझे याद है, इस समय चिदम्बरम जी चले गये, चिदम्बरम जी टाडा लाये थे। वह उस समय भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम थे, जब टाडा आया था और मुझे याद है कि उसका दुरुपयोग कैसे-कैसे होता था। पुलिस वाले को सुविधाजनक लगता था कि इस अपराधी को इस एजिटेशन को, चाहे वह ट्रेड यूनियन का एजिटेशन हो, मैं गुजरात में गया था, जहां पर फारमर्स एजिटेशन के खिलाफ, यहां हमारे दोनों साथी बैठे हैं और पहली बार अगर मैं टाडा के खिलाफ बोला तो उस फारमर्स कांफ्रैन्स में बोला, जहां फारमर्स के एक एजिटेशन को सप्रैस करने के लिए वहां पर टाडा का उपयोग किया गया। लेकिन किसी स्टेज पर तभी हमने यह नहीं कहा कि टाडा को स्क्रैप करो, कभी नहीं कहा। टाडा का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हमेशा हम इसका विरोध करते थे। लेकिन किसी

स्टेज पर टाडा खत्म करो, यह हमने नहीं कहा। मैं उम्मीद करता था कि आप भी हमें यह कहेंगे कि ठीक है, पोटा बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन दुरुपयोग मत करना, ऐसा कहते और अगर कहीं दुरुपयोग होता है तो आप उसे रोकते, उसकी आलोचना करते। लेकिन आपने लगातार अपनी एक थ्योरी बनाई कि terrorism is a law and order issue. स्टेट को करने दो, केन्द्र की जरूरत नहीं है। I can quote Shrimati Sonia Gandhi on this and I can also quote the Home Minister, Shri Shivraj Patil, who is no longer there as Home Minister, on this. But everyone from Prime Minister to Home Minister to the Congress Party President has taken the stand that the present set of laws is totally adequate to deal with terrorism.

And let them deal with it as law and order is a State issue. हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। This is the basic flaw that has been your thinking till today. Today, suddenly when you have staged a 'U' turn, मैं तो बहुत खुश हूं। नेचुरली खुश हूं क्योंकि मैं लगातार आरग्यू करता था क्योंकि कानून हमने बनाया था और जिस कानून को समाप्त करना यूपीए के कार्यक्रम में in respect of Terrorism, लगभग एकमात्र चीज थी कि पोटा को हम खत्म करेंगे। It was the only thing that finds mention in the UPA's Common Programme.

In fact, I have with me a quotation from the Prime Minister. On September 3, 2005, Prime Minister Mr. Manmohan Singh at Chennai had said that :

"His Government had fulfilled its promise to repeal the Prevention of Terrorism Act, which has caused unnecessary harassment to every section. Our Government had made a commitment to repeal POTA, and we have faithfully fulfilled the promise made at the time of last Lok Sabha elections."

होम मिनिस्टर साहब, आपने प्रधान मंत्री की इतनी बड़ी गर्वोक्ति को बिल्कुल नकार दिया।

हमने इतना बड़ा वचन पूरा किया और आपने उनको एक प्रकार से उस सारे को निरस्त कर दिया। क्यों? आप इस बात पर सोचिए। Mr. Home Minister, it is not easy just to nod your head and get away with it.



It is not only because of Mumbai. मुम्बई से पहले जो घटना थी, वह इतनी बड़ी नहीं थी । मैं उस पर कहना चाहूंगा। मैं मन में सोचने लगता हूं कि क्यों, आखिर मुम्बई में ही दो साल पहले लोकल ट्रेन्स पर हमला हुआ था। वह हमला भी कोई कम भयंकर नहीं था और इसके बाद जो पहला वक्तव्य बाहर से निकला था, वह यह था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और उसके थोड़े ही समय बाद अचानक प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान तो स्वयं ही आतंकवाद का शिकार है, victim of terrorism. पाकिस्तान में भी कुछ हमले हुए हैं, वहां के राष्ट्रपति पर तथा दूसरे लोगों पर हमले हुए हैं। But to describe Pakistan as a victim of terrorism, and that too by the Prime Minister and two days later to announce that a joint-mechanism between India and Pakistan be set up to fight terrorism, I was shocked and amazed. हमने कहा कि इतने साल हमको दुनियाभर को विश्वास दिलाने में लगे कि हमारे यहां जो आतंकवाद है, वह कोई होमग्रोन नहीं है, It is cross-border terrorism. और वे मानने लगे थे कि हां, यह सही है। अभी-अभी आकर दो दिन पहले यह कहा गया कि "Pakistan is the epicentre of terrorism." ये जो इतने सारे परिवर्तन हुए हैं, मैं मानता हूं कि कुछ तो सच्चाई है जो किसी को भी देखने में आएगी और दूसरी बात है कि देश में जैसा वातावरण मुम्बई पर उस हमले के बाद पैदा हुआ, फर्क यह है कि इससे पहले के जो विस्फोट होते थे, वे दो-चार घंटों के लिए होते थे। लेकिन इस बार तीन दिन तक यह सब लगातार चलता रहा और उसमें टेलीविजन चैनल्स ने जिस प्रकार से उसे दिखाया, हालांकि वह एक अलग बात है कि उसमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए या कोई उसका कोड बनना चाहिए, मैं इससे सहमत होते हुए भी समझता हूं कि टेलीविजन ने एक प्रकार से बहुत बड़ी देश की सेवा की कि उनको स्वयं लगा कि एक-एक व्यक्ति, एक-एक नागरिक जो टेलीविजन देख सकता था, He failed outraged कि हमारे यहां क्या हो रहा है? यह कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? टेलीविजन ने वह चिंता पैदा की और इसी के परिणामस्वरूप लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। लोगों ने जाकर किसी एक पार्टी के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं किया बल्कि पूरी पोलिटिकल कम्युनिटी के खिलाफ अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। यह इसीलिए क्योंकि

आपने दस साल तक इस बात से इंकार किया कि कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाएंगे।

और स्पेशल लॉ नहीं बनाना और अगर स्पेशल लॉ किसी ने बनाया है, तो उसे खत्म करना, एक प्रकार से सरकार ने आर्टिकल ऑफ फेथ बना दिया। इसका जो नुकसान हुआ,उसे हम लोगों को उस दिन भुगतना पड़ा। लोग यह समझने लगे कि ये सब लोग सुरक्षित हैं, किसी के साथ कमांडोज़ हैं, किसी के पास यह है, किसी के पास वह है, और आम नागरिक दुखी है। एक प्रकार से उनका गुस्सा जायज़ है। यह गुस्सा हमारी सरकार के स्टैंड के कारण है कि किसी कानून की जरूरत नहीं है, आर्डिनरी लॉज़ पर्याप्त हैं, It is a State issue, essentially a law and order issue. It is not a law and order issue. it is a very special evil. और जिस इविल ने दुनिया भर को इफलिक्ट किया है और आज भी किया है। मैं आपको बताऊं कि कितने हमने कानून बनाने हैं? अमरीका ने कितने कानून बनाये हैं, अमरीकन पैट्रीयट एक्ट नहीं, अनेक बनाये हैं। होम सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट बनाया है। मैं इन बातों में अभी नहीं जाना चाहता, जरूरत नहीं है कि जब हम बैठकर डिसकस करेंगे तो सोचेंगे कि क्या करना है? बेसिकली हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि आज अल कायदा जैसे टैरेरिस्ट आर्गनाइजेशन्स, उनका सब से बड़ा दुश्मन, अगर कोई है तो वह भारत नहीं है, उनकी नजरों में अमरीका है, दूसरे नम्बर का इजराइल है और शायद हमारा नम्बर तीन हो सकता है, बम नहीं जानते। उनकी नजरों में सब से बड़ा दुश्मन अमरीका है, भारत नहीं है। लेकिन अमरीका सब से बड़ा दुश्मन होते हुये भी 9/11 में उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली कि उसके बावजूद वहां कोई छोटी-मोटी घटना तक नहीं हुई जब कि यहां पर 2004 के बाद से न जाने कितनी ऐसी घटनायें हुई हैं। मैं अगर गिनाना चाहूं तो ढेर सारी गिना सकता हूं। मैं छोड़ देता हूं। I do not want to hammer the same point today.

I do not want to go into it. I would only like to say कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये लीगल फ्रेमवर्क चाहिये जिसकी दिशा में एक कदम आज उठाया गया है। उसमें भी मैंने बताया कि इसमें मुझे जो इनएडीक्वेसीज़ लगती हैं, in respect of confession लगती हैं। मुझे यह लगता है कि इंटरसैप्टेड इनफार्मेशन के बारे में जो प्रावधान थे, पोटा में जो थे,



आप देख लीजिये, वे अनेक और सब के सब हैं। और इसकी इंटरसैप्टेड इनफौर्मेशन एडमिजिब्लिटी और प्रीजम्पशन ऑफ आफिस के बारे में आपने जो कुछ कहा है , मैं उससे ज्यादा डिसएग्री नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि कुल मिलाकर अमरीका शासन और अमरीका समाज – दोनों का एटिट्यूड बहुत इम्पाटहुर्ट है। हिन्दुस्तान में भी सरकार और समाज तथा सरकार और देश के एटीट्यूड की बहुत इम्पार्टेंस है। मैं एटीट्यूड की बात जब कहता हूं तो 2001 में जो घटना हुई थी लेकिन उसके परिणास्वरूप 2008 में आज भी अगर कोई अमरीका जाता है तो जो आदमी एअर ट्रेवल करता है, उसकी पूरी जांच होती है, अच्छी खासी जांच होती है कि जुर्राब खोलो, जूते खोलो, यह खोलो, वह खोलो। अगर ऐसी स्थिति यहां हो तो क्या हमारा देश इस बात को स्वीकार करेगा? दिक्कत करेगा, मैं देश की बात कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि आज तक क्यों ऐसा हुआ? भारत की संसद पर 13 दिसम्बर, 2001 को हमला हुआ। मुकदमे का फैसला 2002-03 में पूरा हो गया। अपराधी पकड़े गये, सजा हो गई और जिसे फांसी की सजा हुई, उस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, एंडोर्स किया लेकिन इम्पलीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कोई लौजिक नहीं, कोई बात समझ में नहीं आती है। कुल मिलाकर ये बातें एक संदेश भेजती हैं कि सारे आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्यवाही करने में देश ढीला-ढाला है You can get away with it. मैं एक प्रावधान और भी कहूंगा।

जिस प्रावधान का रिकमेंडेशन नेवी कमीशन ने किया था, उसका जिक्र भी आपने किया है। नेवी कमीशन ने यह रिकमंड किया कि जो बैनड ऑरगेनाइजेशंस हैं, नेवी कमीशन में पैटीशन है, लेकिन यह लॉ कमीशन का है। The Law Commission in its 173rd Report also recommended that memberships of banned organisations should be construed as a terrorist act. This is a very serious matter. Therefore, in our Prevention of Terrorist Activities Act we had incorporated that. It is a recommendation of the Law Commission.

Today, particularly before this Bombay incident, with regard to the various incidents that took place in Jaipur, in Delhi, in Ahmedabad, it was said that it is home-grown terrorism now because it is SIMI mainly. This SIMI is a banned organisation, which

in a way got away for a brief while because the Home Ministry failed to give the necessary evidence to the Tribunal. Subsequently the Home Ministry got it stayed and the ban was re-imposed. Today SIMI is a banned organisation even though Members of the Cabinet itself keep on defending it all the while. It is a very strange situation. Therefore, I would recommend that this recommendation of the Law Commission also should be reconsidered when you are thinking of all the inadequacies and shortcomings in the law.

By and large, I would once again say, it is no different from a war. It is a war that we are facing. To succeed in this war there has to be unity. Above all, there has to be a will to win this war. That will has been lacking. Today, if your two laws are an index to show that you have decided to turn a new leaf, to take a U-turn, I would be very happy.

I started thinking as to why the Government has changed its tune somewhat immediately after the Mumbai incidents. Some of the reactions that came immediately after Mumbai and then in the form of these two Bills, and the statements that have been made from the Government side, are different from what was being said earlier. First I am happy that no longer is it being said that an anti-terror law would be an anti-minority law. That is perhaps because you think that you are in power, therefore, it cannot be anti-minority.

Secondly, these terrorists selected three places. Why did they do it? There is a dimension to the Bombay incidents which should be taken note of. The world must have taken note of it. They selected the Oberoi, they selected the Taj, they selected the Trident, which is adjoining the Oberoi. They were sure that in these five-star hotels there must be foreign nationals also. So, our attack should not be only on the Indians, it should identify foreign nationals also and attack them. Then they chose Nariman House. I do not know but I am told that one Minister of ours omitted to mention Nariman House. It was reported in the Press. I do not know. If it is so, it is unfortunate.



Nariman House was selected by them after having done surveillance that this is one place where people from Israel, or all Jews living in Bombay assemble. In fact, the Israeli Ambassador when he met me told me that it was a Wednesday; if it had been a Friday, on Friday night on the eve of Saturday, which is their Kosher Day, if all the families in Bombay had assembled there, the tragedy would have been much bigger, much larger.

Foreign nationals were being targeted; Indians, of course, were targeted. So many people on the Chhattrapati Shivaji Terminus, coming from trains from all parts of the country, two terrorists with AK47 in their hands, went on mowing them down, killing everyone. The whole thing was horrible. Is it that we have woken up because it is not merely the people in India who think that India has become unsafe because of this soft attitude to terrorism, but the whole world thinks that India is now unsafe to the attack of terrorists? Is it this that has made us react in the present manner? I would think that the Security Council Resolution of 2001 was a very sound Resolution and those who followed it, did something in the interests of their own country, in the interest of humanity and the right step against terrorism. I am sorry that we should have been criticized because of following this particular UN Security Council Resolution in letter and spirit and enacting a special law to deal with terrorism.

With these words, I am grateful to you, Sir, for allowing me to initiate this debate.

■

# UPA's change of heart, wellcome

## Arun Jaitley

Mr. Deputy Chairman, Sir, I am extremely grateful to you for permitting me to speak on these two Bills, the first seeking to create a National Investigation Agency and the second Bill amending further certain provisions of the Unlawful Activities Act. Sir, I must confess that I speak with a mixed feeling. The mixed feeling is that my party and others who support us could derive, at some stage, some sense of satisfaction that, at least, in some areas, if not all, what we have been very strenuously saying for the last four years and seven months that a strong legal mechanism also required to investigate and punish terrorism. The reason and rationale that we have set out for this, at least, a large part of what we have said, has now been finally accepted by the Government. We might even get some satisfaction from the fact that most of the arguments which were used to repeal the erstwhile anti-terror law, POTA, are now proving to be spurious. We can also get satisfaction, as a country, from the fact there is a near unanimity, both within the country and outside, as well as, in this House and in the Lok Sabha, that these two legislations are required. But we are, at the same time, concerned about the fact that the measures which the Government have taken are still not strong enough and still falls short in a large measure as a legal mechanism for fighting terror. Sir, we are also concerned and, I am sure, every Indian is concerned about the fact that what has brought this consensus is not really the sound and strong logic that we have been giving to this Government for more than four-and-a-half years now. Where reasoning failed, where our rationale failed, I think, the ten evil



men who entered Mumbai on 26th November and shook the conscience of the whole country succeeded in persuading the Indian society that India can no longer afford to be a soft State and must finally start adopting hard measures if it is really serious about combating and fighting terrorism.

Sir, I remember that there were different reasonings given why India did not need a strong anti-terror law. When POTA was repealed -- I was looking back at the debates -- and even when it was first introduced -- I was reading the debates -- the country was repeatedly told by the opponents of a strong anti-terror law that a strong anti-terror law is not per se against terrorism, it is against minorities. The country was told that normal laws in India are enough to tackle terror and when you have so many normal laws why you need a special law to tackle terror. The third reasoning made out was that a special anti-terror law per se would be opposed to the constitutionally guaranteed rights and, as a Republican Constitution, we can't afford to have a strong anti-terror law. We were then told that there is a huge scope for misuse and abuse of this law and since there is a scope for misuse and abuse of this law, it is much better to go by the normal laws and not have this law.

Lastly, Sir, an argument was repeatedly raised and I have seen a large number of my friends raising this argument till the other day in and out of this House that anti-terror laws don't prevent terrorism; despite POTA, an attack could take place on Akshardham, an attack could take place on Parliament. Since despite an anti-terror law, attacks can still take place by terrorists, what is the point in having a special anti-terror law? Sir, I repeat that the ten evil men who entered Mumbai on 26th November have shaken all these fundamental assumptions on the basis of which a strong anti-terror law was being opposed. Today, with the kind of measures which have been announced, plus some additional measures which have still not been taken by this Government in this law, it appears that the Government now also believes that all these assumptions, which were being given to

oppose the strong anti-terror law, were really spurious assumptions; they were fallacious assumptions.

Sir, it is obvious to anybody who understands how a fight against terror and insurgency can take place that a battle against terrorism is not fought in the courts of law. Terrorism is not something that can only be fought through legislation. An anti-terror law is never a substitute for a strong preventive intelligence. An anti-terror law is never a substitute for a strong security action and a quick reaction commando action against terrorism itself. To fight terror you need a large number of steps. If it is cross border terrorism, if it is internationally engineered terrorism, you, perhaps, need a global consensus. You may even take foreign policy initiatives and work for a global consensus for sanctions against countries and States which encourage terrorism. You require a very strong intelligence network to fight terrorism, not only within your own country, you require a strong intelligence network which infiltrates into the enemy camp and pre-warns you of what is likely to happen. Then you require that intelligence to be shared with those who require that adequate intelligence information for the follow up action to be taken which, at times, we find we are lacking in not taking that. What do we do to our security responses? The law is not relevant. Our quick security responses, our immediate security responses really determine it because if we take action after hours, the terrorists have already won. They have created a global impact; they have created a national impact.

Therefore, these are essentials which are required to fight terrorism. An anti-terror law or a machinery to investigate terrorism, whether it is a Central agency or a State agency, comes into the picture not as an agency or a law which can prevent the act of terrorism, it is not an agency which can really start distributing intelligence all over the country, it is not an agency which will per se have a security force at its disposal to prevent terrorism, that has to be done by the various agencies which are earmarked for this purpose. The law and the agency comes into the picture, either just about when an act is being planned or when an act has



just been committed. Therefore, for the purposes of collection of evidence, investigation of that crime, punishment of the criminal, you need a law and you need an agency which is effective.

You need a law which can adequately collect that evidence, which can bring out that evidence and put it at the disposal of the prosecuting agencies. Then, the conviction of those involved in acts of terrorism becomes simpler and easier, so that your conviction rate goes up. And, when your conviction rate in terrorist offences goes up, then, it is a deterrent for those, who commit acts of terrorism, not to indulge in those acts. The preventive impact of this law is that it reflects the determination of the Government and the Indian State in fighting terrorism, and the Indian State is then adequately equipped in terms of law, to investigate the crime and expeditiously punish those who are responsible for that crime. As I said, the battle against terror is never fought exclusively in courts or through legislation.

You have to first equip the minds of the Government and the agencies of the Government. It is in the hearts and minds of the people of India that they must get ready, that we are a State, which is on the terrorist radar, and, therefore, we must equip ourselves to fight terror. It is through these Acts that the determination of the Indian State, in fighting terror, is expressed. Unfortunately, 95 per cent of the tenure of this Government is over, and that 95 per cent of the tenure of the Government had been spent in convincing each one of us as to why a strong terror was not required, and different arguments, as I have already explained, were advanced to establish that these were not essentials which were required, and an effort was being made to dilute the whole thing. I am afraid even though the Home Minister's Bill indicates to the contrary what some of his colleagues have been saying, it still indicates, and that is where we are concerned about, that the battle against terrorism is to be diluted because they think that the battle may prove to be politically costly, and, therefore, the vote bank signal, which has to be given, is to the contrary Yet, I don't think it is a matter where any one of us can really be amused

because the argument really is that when you have both Houses of Parliament debating on this Bill, at the same time, you have a colleague of the Home Minister, making a statement yesterday, which was flashed on all front pages of the newspapers of our Western neighbour, and the blogs coming out of Pakistan were full of it saying, "Look; we always said so."

Now that is the signal which I am referring to. And the Government, spent 95 per cent of its recent tenure giving this signal rather than taking substantive steps in fighting terrorism. Sir, even though we found some aspects of this law to be inadequate, -- my party had announced very categorically that we would support these Bills -- even though we said that these were only half-a-step, we would support this half-a-step against terror but would continue to campaign for the other half, the seriousness of which the Government may not have realised. I am conscious of the fact of what the newspaper reports that the Home Minister couldn't really be blamed for it, if they are to be believed, it indicates that he tried his best to get some more provisions, but some of his colleagues were, perhaps, concerned with the forthcoming elections rather than the security considerations which are in-built in those provisions.

Unfortunately, we have a Cabinet which has too. Each ally of the Government seems to be taking credit for diluting this Bill. Sir, I am glad that the Home Minister has clarified these because then, I would like to withdraw the little compliment that I gave him, when I thought that, at least, he had realised the seriousness and the gravity of the situation and tried to bring in something which he honestly admits that he did not bring it. Sir, in order, therefore, my primary task would be to convince him so that he can convince his colleagues as to what further is required to be done, as far as these laws are concerned. Sir, in order to just simplify the issue, let us, for a moment, before I go into the abstracts of what is required and what is already there, just discuss and place before this House that what is the essential which is required in the investigation of a terrorist offence? A terrorist offence per se is not like



an ordinary crime where eyewitnesses would be easily available. A terrorist offence per se will have conspiracies, at times, which are hatched in foreign soils. You will have some people, the fidayeen, the jehadi terrorists, the suicide squads who are not scared of dying, who are not scared of the prohibitions contained in the law, who are not even scared of the consequence of the law. Therefore, you will always have a larger conspiracy behind the apparent terrorist acts. We can analyse anyone of the terrorist cases which have recently taken place. Let me just point out a glaring terrorist case, recently took place in Mumbai on 26th of November. On the surface, ten terrorists came by the sea route, attacked various vital places in Mumbai. Nine out of the 10 are killed, one is arrested. What happened in Mumbai is extremely easy for the Indian police to prove. You have eyewitnesses; you will have various other evidences; you will have reports of experts, and it won't be a difficult task for an Indian investigative agency to prove it against those ten. But, nine out of the ten are, unfortunately, not there. It is a rare case that a terrorist has been caught alive. Ordinarily, they are not caught alive. But, the real conspiracy is not merely those ten. The real conspiracy in this case is, and that is where the law is lacking, who were the people who trained these ten across the border? There were obviously some training camps where for a year or a year-and-a-half, these people were given extensive training; funds were made available to them; their families were assured that monies would be given to their families, in case anything happened to them; weapons and equipment were supplied to them; RDX was supplied to them. It is possible that such an operation could not have been carried without the support of the official agencies. Who were these people who organised the entire conspiracy across the border? Pakistan is living in denial. Their High Commissioner made a statement yesterday, their Foreign Minister made a statement yesterday that Masood Azhar is not in Pakistan, conflicting what had been said earlier. Pakistan as a State which is living in denial will continue to deny it. Pakistan does not seem to be in a mood to render cooperation. Therefore,

the responsibility is ours, the onus is on us to prove the Pakistan link and the Karachi limb of this conspiracy.

Now, the terrorist who has been caught alive is speaking. His statements are being published, and his statements are being shared with the entire world. But, under this law, with adequate safeguards, and I underline and re-emphasise the word 'adequate safeguards', if Kasab's statements to the investigating agencies are not evidence, then, we may well be reading just a news in a newspaper which is not evidence in a court of law And Pakistan would then turn around and say, "What Kasab is saying is not evidence under your own law, in your own country, how do you want the international forum make it as evidence against me?" Let us move a little backwards. One of the most glaring cases in India is of the late Shri Rajiv Gandhi who was assassinated. When Shri Rajiv Gandhi was assassinated, TADA was in force. Though eventually the Supreme Court did not convict them under TADA because of some interpretation of the definition of TADA, but the Supreme Court still applied the rules of evidence of TADA. The lady with a human bomb killed Shri Rajiv Gandhi on the spot. The actual killer died on the spot. 50,000 people witnessed that killing. Yet, when the matter came to court, our SIT went to the first conspirator, those who supplied the vehicles, those who supplied the arms, those who supplied the shelter, those who harboured them, and those who planned the conspiracy; our SIT got all of them. Our SIT did a remarkable job in reconstructing the whole crime. And, finally, just as we do not have any eye witnesses of what happened in Karachi or the terrorist training camps, the SIT did not have any eye witnesses of what the conspirators were doing behind the closed doors. Conspiracies are hatched in darkness. They are behind the closed doors, they do not leave eye witnesses behind.

So, it is only when the first conspirator sang, the second conspirator spoke; their evidence under TADA became admissible evidence and the conviction of the other accused in the Rajiv Gandhi assassination case took place only because of the admis-



sibility of those confessions. Take those confessions out, and this country would have been a laughing stock where a former Prime Minister is assassinated in front of 50,000 people and you would not have a conviction in the case!

The actual assassins had died on the spot. Take the Parliament attack case. The five actual persons who attacked the Indian Parliament died within this premises itself. It is the conspirators who were arrested. The most material evidence against the conspirators is those who spoke--the first and the second men who were arrested. This is not only in this case, I will come to it a little later; what is it which requires a strong anti-terror law? I always tell my friends in the Government that when India is on the terrorist radar, you do not have to be apologetic about India having a strong anti-terror law. We are supporting this Government on the anti-terror law. But the difference between the ruling benches and the opposition this time is, the opposition is supporting this Bill as a national necessity and the ruling party is still embarrassed and is apologetic about having brought this Bill! That is the difference. It is a strange dichotomy in the Indian democracy which has taken place. We are more enthusiastic about what the Government is bringing, this type of Bill! Now, you require an anti-terror law, and the Government had repealed the POTA. But, then their security experts told them, "Why are you making India so vulnerable?"

Sir, I did an exercise as to what was there in POTA. Of course, I am conscious of the fact that such a remedy is not available; but, if for hijacking or copying an Intellectual Property, an action was available; I think, the NDA had a strong case against the UPA. We drafted a law, they said, "It is a horrible law and we will repeal it', then took a scissor and started a cut-and-paste exercise by culling out provision by provision from POTA, and word by word, full stop by full stop; and if we had left the grammatical mistake somewhere, along with that grammatical mistake they started incorporating it in the Unlawful Activities Prevention Act. I just started comparing the features; on the language, the verbatim lan-

guage is the same. The law must define terrorism; they had repealed POTA which defined terrorism; so, they picked up that definition and put it in the Unlawful Activities Prevention Act.

POTA was criticised because it had an extraterritorial application. Obviously it is needed because if one limb of the conspiracy takes place in Pakistan, the anti-terror law will have its extraterritorial application. So you brought it back by 2005 amendment. The quantum of punishment required under POTA, you picked it up and brought it back. Now, besides an act of terrorism we said whoever abates terrorism, whoever incites terrorism will also be an offence, though a lesser offence, they picked up the language, pasted it in another law; harbouring terrorists, they picked up and pasted in another law; membership of a terrorist organisation, again picked up from POTA verbatim and put in another law. Confiscation of proceeds of terrorism now, this was based on a salutary principle that no person can benefit from profits of crime. You commit a crime and out of the profits of that crime you buy a house or you open a bank account where you keep money, so, that properties will be confiscated if they are out of terrorist funds or those will be confiscated, they said it is a very good concept let us put it back. If you threaten witnesses in a terrorism case, that also is an offence -- verbatim taken and put in the Act. Declaration of an organisation as a terrorist organisation -- picked up the provisions verbatim and put them in the other Act; special laws -- picked up the Sections and placed them in another Act. And then let me compliment -- the Home Minister is not here, Mr. Sibal is here and Mr. Sibal's favourite argument is that my law is better than your law, so the remand period being provided ....

Mr. Sibal's argument, which I have been answering for the last four-and-a-half year, is that special law is not required. Mr. Sibal is a man of principles. You see, he opposes it on republican principles, brings this law on the principles of preserving national sovereignty. In any case, he stands by those principles and he will justify his principles at all stages. I think in that event with all these



provisions had to be brought back. If all these provisions had to be brought back, there was no need why India should be made so vulnerable for four years and seven months. ...(Interruptions)... For four years and seven months you made this country vulnerable and then you decided to bring the same law back. ....(Interruptions)... Then, Sir, the said, well, there is a remand period mentioned in the old law, we will have a discretion for larger remand period. Well enough, because if the investigation does not conclude in 90 days, you may require 180 days and therefore, you may require to get evidences internationally, you may have to send letter rogatories across the globe to get evidences, you may have to get people extradited other countries, therefore, longer period of investigation will be required Therefore, they put a provision of giving some element of flexibility, yes, longer remand is required. It is a correct provision in law, I have no difficulty with that. On dozens of occasions we have been told in this House that you turned the law upside down by shifting the onus of proof. There are no presumptions, which are available. Now the presumptions available in POTA have been exactly brought back. And what are those presumptions? The Evidence Act has those presumptions. There is a chapter on presumptions in the Evidence Law that if a weapon is found in your possession, the presumption is there unless you disprove the fact it is not yours. The fingerprints found in a vehicle, on the steering wheel of a vehicle, which is used for terrorist offence, the presumption is you have used that vehicle, the onus is on you that you have not used that vehicle. Section number has been altered, Sir, that presumption now is back.

Confiscation of passport, setting of review committees, in fact, POTA had a very interesting safeguard with regard to intercepts.

Obviously, a large part of criminal law investigation these days are done on the strength of taking telephonic conversation and intercepts. Now, doubt arose whether these are admissible evidence. But POTA provided a safeguard. The safeguard under POTA was, if a police officer wants to intercept, then, from the

competent authority he must take sanction and every fortnight the Review Committee headed by a judge will certainly get the total record of people whose intercepts have been made and these intercepts will be admissible evidence in a court. You went a step a further. You said no sanctions are required. The intercepts from wherever you get are admissible evidence. Well, the police was facing a difficulty. If you want to go that far I have no difficulty, we will support you even on that. But don't be apologetic on the fact that India didn't need a strong anti-terror law. It is an admission of the fact that you made this country vulnerable for four years and seven months and now you come back to say, 'well, India does need a special law. You cannot fight terror with ordinary laws.' Sir, there were two vital provisions left out and the two vital provisions are one with regard to special bail provisions and the second with regard to confessions. Sir, as far as bail provisions were concerned, under your normal criminal law you have the bailable offences, the non-bailable offences where the discretion is with the court. There are special laws in which the discretion of the court in granting bail is further reduced. The court can't grant bail till a public prosecutor has been noticed and if the court comes to an opinion at the stage of bail, that prima facie the case is true or prima facie the case is not false, just a prima facie view, the court will not grant bail. Now, we had been repeatedly saying you require a stronger provision because once a terrorist gets bail and if he is an international Jihadi, after getting bail he is not going to come back and say, 'well, I am coming back for the purposes of getting executed in India.' So, he is certainly going to jump bail. Therefore, why do you not have special provisions with regard to bail? Now, the present law has brought that provision back.

But, then, the UPA is not NDA, so you have to be different. The earlier law said prima facie the case against him is not true. The judge will not grant bail. You said he would not grant bail if he were proved that prima facie the case against him is true. So, one had a direct mention and the other alternative as double negatives. The two mean exactly the same. You said, 'well, we have a



different bail provision now and you brought back and there is nothing wrong in this bail provision. Sir, I have just prepared a list. TADA had this bail provision. POTA had this. But, besides an anti terrorism law there are at least 12 laws in India which have the same bail provisions. The MACOCA has the same bail provision, the Andhra Pradesh and the Karnataka Organised Crime Laws have the same provision but the Government said we are against these organised crime laws so we are not allowing some BJP ruled Governments to have those laws. But, your Narcotics Act has the identical bail provision. Not only the Narcotics Act, I have copies, Sir, you have similar bail provisions besides the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, Scheduled castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, Anti Hijacking Act, Prevention of Damage to Public Property Act, Prevention of Money Laundering Act and, then, even Suppression of Unlawful Acts against Safety of Maritime Navigations. You have the same bail provisions which are the extraordinary hard bail provisions, Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation, Terrorist Affected Areas Special Courts Act and, finally, even the Wild Life Protection Act.

So, those who commit these offences against the wildlife would not get bail. But, those who committed these crimes against humanity, terrorist offences, were entitled, under this Government, for four-years-and-seven-months, to a lighter bail provisions. They say, 'No. We would not have it.' Finally, I think, where all our logic and rationality failed, you have those ten evil men who came on 26/11 convincing the whole country and then pressurising this Government to, reluctantly, come up and strengthen the bail provisions.

Sir, even confessions, on the face of it, looks a little alarmist. I concede to this that, ordinarily, in a law, confession to a police officer is not admissible evidence. It should not be. That is the normal law. In all our laws this should be the general principle. But, we, in India, have exceptions. We, in India, even today, have exceptions. Sir, TADA and POTA were exceptions. The MCOCA

is an exception. The Karnataka Organised Crime Law is an exception. The Andhra Organised Crime Law is an exception. The Narcotics Law is an exception. You make a statement to an officer investigating a narcotics offence, your statement is admissible evidence. You make a statement to a customs officer, it is admissible evidence. You have in foreign jurisdictions in liberal democracies these statements become admissible evidence, provided Judge is satisfied with regard to the voluntariness of the nature of confession. And, the Supreme Court said -- it is extremely important.

If, obviously, the confession is involuntary or appears to be involuntary, it should be disregarded. But, they say, how do you then ensure that there is no misuse? Sir, four guidelines were suggested. The first one is, the officer recording the confession must be a Superintendent of Police or above. The second one is, it must preferably be video recorded or audio recorded. The third one is, within 24 hours or 48 hours, as the Government decides, the accused must go before a judge after making the confession. The Judge will ask him if it is voluntary. If he says that it is involuntarily, he will be examined medically. All these factors will be considered in order to determine the voluntary nature of that confession. Now, on the one hand, you have an extraordinary crime and that extraordinary crime is a crime against the State, a crime planned in secrecy where there will never be an eye witness. I repeat, those who conspired in secret meetings to assassinate Late Shri Rajiv Gandhi, no investigation could ever produce eye witness of that. One of them had to speak. And, if his statement was not evidence, then, there would be no evidence. If Kasab's statement is not evidence, then it is extremely difficult for India to prove what happened in Karachi or the Pakistan's limb in this conspiracy. When you have gone so far, why do you stop half way? When you want to create a National Investigation Agency, why don't you give teeth that it needs in order to investigate a crime and produce him before the world and the Indian courts evidence required in relation to these crimes? Sir, if these essentials are not



there, then, I am afraid, even though, we move half a step further, there will be cases and cases where we still fall short. There are enough people waiting really to find holes in the Indian case. I am not referring this to as a police case. At times, we are in the habit of discussing, well so many attacks took place when you were in power, or, I was in power or somebody else was in power. This is the Indian case. There are enough people waiting. You have articles and books written which says that attack on Parliament was organised by the RAW and the IB.

You have Indians authoring such books. Articles in newspapers suggest this. We may all be magnanimous and willing to pass out yesterday's statement of Mr. Antulay merely as an irresponsible act or something where he, perhaps, did not adequately express himself.

But, then, his statement is a huge fuel for the country which has been extending facilities to the terrorists in action against India. Read the blogs in Pakistan today. (Interruptions)

Sir, I think, Mr. Sibal is right. I really should not have named him. The Government itself should have named him today morning. But this is something that has embarrassed this country. This has weakened our case internationally. This is something that defies the collective responsibility of the Cabinet; something that provides ammunition to our enemies and opponents. And, therefore, I should not name him, the substance should be the Government itself should have come up and shrugged off its relationship with a person who makes this kind of a statement. (Interruptions)

Sir, therefore, today, on a strong anti-terror law, where are we? The whole country was misled that we did not need a law. The law was repealed. Then, sentence after sentence, clause after clause of that law was brought back. But, then, you also wanted to have that one upmanship and say, "Well, we are different because this one provision was not there. And, this one provision is a significant provision." Unless that provision is there with safeguards, in case after case, you will be weakening India's case. And, I reiterate and say if that provision had not been there in the

TADA, the accused in Rajiv Gandhi's case would have benefited. If it had not been in the POTA, the accused in the Parliament case would have benefited. Fortunately, Mumbai has the MCOCA which has that provision. But for some reasons, I am told, the MCOCA has still not been pressed into action in the 26/11 case.

Unless that statement is a statement under the MCOCA, which becomes evidence, the Karachi and the Pakistan limb of the conspiracy may be difficult to establish in law. Therefore, we require to do that. So, please re-consider, when you have travelled all this distance and wisdom has dawned on you in the last five months of your Government, and please don't make it an incomplete statement. The Home Minister was candid enough to say that he had consultations with the Opposition. We made it very clear to him that we will, come what may, support it even if it is half-a-step. We have our own nationalist credentials, therefore, we don't want to stop even half-a-step. But, then, please make India a strong State. This law per se will not abolish terrorism. Merely because we have an Indian Penal Code, crime has not ended; because we have section 302 that provides for death penalty or life penalty murders have not stopped. Murders are still taking place, but the law provides a deterrent in a civilized society. It provides an expeditious methodology of investigation and punishment. Therefore, please give this law more teeth than what exist today.

Sir, the second part of the amendment in the second Bill is the setting up of a National Investigation Agency. And, I have said, as far as the first law is concerned, we have supported it because it is half-astep. We have reservations about what has not been done and we will continue to campaign for that. But as far as the National Investigation Agency is concerned, I have no hesitation in saying that we fully support the proposal as has been mooted by the Government. And, this is for two good reasons. First, some doubts are, at times, raised whether the Central Government possesses the power to take over what appears to be a power within the State jurisdiction. The constitutional entries make it very clear that the defence of India, in List 1, entry 1, is the exclusive pri-



mary domain of the Central Government; and, it is the public order, which includes the law and order, which is in the domain of the State Government. Where does terrorism fit in? Terrorism is not merely law and order. Terrorism is something which attacks the sovereignty of India and it attacks the unity of India. Therefore, if there is cross border terrorism of this kind, it has something directly to do with the defence of India. Therefore, even in the Supreme Court, when TADA was first enacted and POTA was first enacted, an objection was taken with regard to the legislative competence of the Centre to enact an anti-terror law on the ground that law and order is a State subject. But the Supreme Court also said that there is no entry called terrorism in the Constitution. Therefore, this could, perhaps, come within the defence of India and not public order. If it doesn't fall in either, then, it comes within the residuary entry, List I, Entry 97. Therefore, this is, exclusively, within the central domain. Protecting the sovereignty of India is the responsibility of the Central Government. Therefore, against terrorism, if a law is brought, it is within the Central domain. If an agency is created to investigate that offence, then, obviously, those who have the competence to enact a law also have the competence to create an agency of that kind.

Therefore, we fully support the Government's proposal that the Central Government is fully competent to enact this law. Even otherwise, Sir, an offence of terrorism in some cases may not adequately be investigated by State police. There may be offences which have inter-State ramifications. You may require sharing of intelligence between several States. You may require coordination of intelligence of all those States. You may have different limbs of the conspiracy in different States. You may even have, -- as this law has extra-territorial application; some parts of the conspiracy taking place outside India -- some intelligence required from outside India. Now, there may be offences where all this is not present and the Central agency itself may feel the State police can do it. But in extraordinary cases like the one in Mumbai, or, the Parliament attack, these may be cases, where State police itself may be

inadequate to investigate the offence. And, by the very nature of the offence, a Central agency would be more competent in order to investigate that offence. Therefore, we fully support the proposal of the Central Government as far as creation of a central agency is concerned with a discretion that some extraordinary offences of this kind, when they take place, the central agency itself will investigate those offences.

Finally, Sir, let us realise one thing. While we are debating this law, this country has paid a huge cost of terrorism. We have lost individuals, we have lost human lives, and we have lost lives of security personnel. A large part of our national resource gets spent on it. Where there is terrorism, investment is not forthcoming. The economic resources are diverted to fight terrorism. You may even have a diversion as far as your defence preparedness is concerned, where instead of looking at your borders, you are looking at your interiors where terrorist activities are taking place. Anti-insurgency steps, anti-terror steps, at times, are strong. Mr. Chidambaram was right when he says that we have to do a balancing act between human rights and fighting terror. Therefore, there may be some erosion, at some stage, of individual rights. Harsh combing operations, at times, lead to alienation of local population. These are all costs we have to pay because of fighting terrorism. Therefore, when this is the kind of cost this country has to pay, I think, we need not be -- while we should be concerned about human rights and balance them in our fight against terror -- apologetic in a state whose sovereignty is threatened in taking strong anti-terror steps. This Government has decided that they have a change of heart. Though what they failed to do for four years and seven months, those ten men who came from across the borders have persuaded them in doing so, and they have brought this law. But, then, let it be an adequate exercise. It can't be an incomplete exercise. As I said, we, on this side, support these measures as one of national necessity and the Government should not be apologetic about having brought in any of these measures.

Thank you very much, Sir. (Ends)

■





# Public anger made UPA act

**Kharabela Swain**

Sir, like the hon. Leader of the Opposition, I support both the Bills. The fCne is the National Investigation Agency Bill, 2008, and the second one is the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2008. During the course of the debate, most of the hon. Members from the Ruling Party made a point, very ably led by one of the most eminent lawyers of this country, Mr. Kapil Sibal. I am happy that he is here to listen to my replies to what he has said.

Generally he does not do that. But after making the speech he always vanishes. So, I am happy that he is present today.

The entire House knows as to who stays and who goes. So, I need not elaborate upon it.

He said, and he was ably supported by Devendraji and others, that everybody should be united in the fight against the scourge of terrorism. What do they mean by that? Do they mean that in order to show our solidarity we will simply go by whatever the Ruling Party says and we will not oppose this Bill? Is this the meaning of unity and integrity? In that case, what is the Opposition here for? If we do not point out the lacunae that are present in the Bill, what are we here for? So, when we say that we support the Bill we also say that if the people of this country bring us to power after some time, we will replace the lacunae contained in this Bill. But, for the time being, we support this Bill.

Hon. Kapil Sibal made a very pertinent point at the fag end of his speech. It was repeated by Devendra Prasadji. They said that terrorism will not end with the passage of these Bills; it requires

will power. Very good! Will power! The UPA Government has been in power for the last four and a half years. There have been terrorist attacks on this country twenty five times in that period. I put some simple questions to the Government. How many terrorists have been apprehended by now? How many of them have been prosecuted? How many of them have been tried in the court of law and how many of them have been convicted? If there is will on the part of the Government, in these last four and a half years how many terrorists have been caught?

Now, all of a sudden, the Government says that they have brought in this Bill because they have got the political will. Why has this Bill come all of a sudden just three-four months before election? That is because firstly the election is very near, and secondly because the entire nation is bubbling in impotent anger. I deliberately use these words 'impotent anger'. Their anger is impotent because they find that the Government has failed to protect them; the Government has failed to protect their lives; the Government has failed to provide them safety. This is the basic reason which has hit them. Because election is round the corner, the Government has all of a sudden brought this Bill.

Mr. M.K. Narayanan is the National Security Advisor. How many times has he said that this country needs a special law to counter terrorism? Will they answer that question? They have summoned all the Directors-General of Police several times. The DGs have demanded that there should be a special law to fight terror. It had fallen on the deaf ears of this Government.

Now, they referred to Mr. Veerappa Moily, Chairman of the Administrative Reforms Commission.

What has he mentioned? He has said in the Report that the anti-terror laws in this country have become toothless. Because they are toothless, terrorists are finding many loopholes and they are getting away. This is what the Administrative Reforms Commission have recommended. The DG, Police, the National Security Advisor, the Administrative Reforms Tribunal – all of them which belong to this Government - have recommended, not one



month or two months before, since years. And they did not listen to it. Now, Shri Kapil Sibal says that they are learning with experience. Even they say and the people say ideologies – you go through his records.

During the course of his debate, Shri Sibal, along with Shri Devendra Prasad, and Lalu ji was also sitting there in front of him, many times they repeated. Not only today, they have also been repeating it several times that the NDA Government had let off the terrorists at Kandhahar. Yes, we did it. Several times, I have asked Shri Sibal, that by telling these things do you mean to say that we had committed a mistake and we should not have let them off. We should have retained them in the Indian jails; we should not have allowed them to go in exchange of the people who were hijacked. Then, what is the meaning? The meaning is, if we do not leave them, there are only one alternative – to let 150 or 160 passengers who were hijacked to get them killed. I told them several times. Yes, Mr. Minister do you want some such thing?

I did not say anything. These hon. Members told. You can go. I will be happy. I am not preventing you. It is not mandatory for you to listen to me.

I am putting this question. If they are so adamant in repeating the same thing again and again that the NDA Government had committed a grave injustice and mistake by just letting off those terrorists at Kandhahar, then, let them say make a simple statement on this floor of the House that we should have allowed these 160 people get killed and we should not have allowed these three terrorists to go off. Will they do it? I have posed this question several times. No answer was given.

They had learnt a very good lesson from their Left friends because in the 'red book' it is written that a lie repeated 10 times, it becomes the truth. They go on just repeating because they were with them for a pretty long time.

So, they just go on repeating the same thing again and again, thinking that it would automatically become the truth.

But any number of times, you raise this question, I will again

put the same question to you –you declare on the floor of this House that it would have been better to have all those people killed.

As regards me or many of the persons in my Party, we do not find any third alternative. When Md. Salim becomes the Defence Minister or the Foreign Minister or the Home Minister of this country, he would find out a third alternative. At that time, we would listen to him.

One of his colleagues, Shri Gurudas Dasgupta asked as to why 180 days. Why did you keep it for 180 days? Are these the canons of democracy? He is a great votary of democracy and a great votary of Nandigram. They are talking about democracy, providing the benefits of democracy, but to whom? Is it to provide values and benefits of democracy to the terrorists, who want to kill the process of democracy?

Shri Kapil Sibal is talking about human rights, but human rights to whom? Is it to the terrorists? He is talking about the human rights to terrorists. Why these things happen in this country? If you want to listen, please listen from me because this is our point of view. The reason why terrorist attacks are taking place in India again and again is this. What crime have we committed?

They say that there are softer laws in the USA and the UK. But why did only once the terrorist attack take place in the US? A country like the USA has totally finished two Muslim countries and there is no second attack! What crime have we committed? What mistake have we committed, to have the terrorist attacks again and again?

I will just read from The Times of India. It is dated 14th December, just 2-3 days back. It is written by Indrani Bagchi has written:

"What is the strategy of LeT? If you look at the LeT strategy, it is to weaken India and to help establish Khalifat which is a part of their ideological programme."

This is not a communal paper. This is 100 per cent a secular paper. It is not Pioneer. It is The Times of India.



Shri D.P. Yadav is present here. What was his argument? He said that there was no distinction between communalism and terrorism. What is its meaning?

He meant to say that because of Parties like BJP, Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad and Sangh Parivar, the Muslims or Islamic terrorists are attacking India. There is a meaning in this. Now, he has also said that there is no distinction between the people of India and the people of Pakistan. The people of Pakistan are one with the people of India.

There was a coup in 1999 when Shri Pervez Musharraf drove out the then Prime Minister Shri Nawaz Sharief from power. When he drove him out he was broadly supported by the people of Pakistan. He was democratically elected Leader and was driven out but the people of Pakistan did not support him. It is only because it was Nawaz Sharief who brought back the Army from Kargil. It was Shri Pervez Musharraf, who was a hero.Give me some more time. I am the only speaker. This is the mind set of the people.

I would like to quote from Times of India of 14th December a report by Ayesha Tammy Haq, a Pakistani. "Social worker Anila Shah says India should address issues raised in the Sachchar Commission Report. We need to deal with our problems at home". What does this mean? Is it that the Muslims are being tortured in India? The Government of India had set up the Sachchar Commission which reported that the condition of Muslims is very poor in India and that is the reason why they are in favour of terrorists. This is what the people of Pakistan say.

The major point that I would like to point out is, even though this Bill has been brought in, my apprehension is that this will not be implemented. It will not be implemented because the Government does not have the will power. The Government does not have the will power because for the last many years it thinks that if it investigates against the terrorists, apprehend them and put them behind the bar then the Muslims of this country will be annoyed and they would not vote for it. This is the only reason why

the Government has not tried to apprehend any of the terrorists. Just because the election is coming, all of a sudden the Government has brought in this Bill.

There is always a sense of persecution mentality. Most of the Muslim intellectuals in this country are of the view that there is a perceived sense of persecution, very ably supported by all these secular members. They think that because of Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad the Muslims of this country are being persecuted. You have said the Muslims of this country are not terrorists. We also say this. We did not say that every Muslim can be condemned as a terrorist. When there was Batala House incident, where two of the terrorists were killed, most of the Muslim leaders including the Congress Party said it was wrong. They said that the police encounter was false. They even said that Mohan Chand Sharma, the Police Inspector who was killed, was not killed by the terrorists but by his own colleagues. What are you going to achieve by this? Are you not raising the false sense of persecution mentality among the Muslims in this country?

Are you not inciting it? Mr. N.K. Narayanan, your own National Security Adviser said that the Police encounter was correct.

Now the hon. Minister of State for Home Affairs, Shri Jaiswalji is sitting here. He first made a statement in the Rajya Sabha that 50 lakh Bangladeshis have infiltrated and then he withdrew his statement.

Now everybody knows Huji and ISI. It is mostly entering into India through the porous border of Bangladesh. Everybody is saying that this is happening. Again I would say that the Muslims are not to be branded as terrorists but just one day before when Prof. Kader Mohideen who is an hon. Member of this House from Tamil Nadu was speaking, he said that there is no Bangladeshi infiltration. An hon. Member from Assam who was sitting at the back bench was telling that all the Muslims in Assam have come to Assam prior to Independence or 100 years back and there is no infiltration. So, when you are making a statement like this, are



you not inciting false sense of discrimination against Muslims? Why should an Indian Muslim allow a Bangladeshi Muslim? If you say that the Muslims and Muslims should enjoin, then why there are separate countries like Pakistan and Afghanistan. Why do they just not join together?

When a prominent Member of the Muslim community like Mr. Salim says like this, in a very subtle way he is justifying the terrorists.

Sir, the terrorists are very cunning. Deliberately they have not attacked West Bengal because they know that....

Sir, they are the facilitators of the Bangladeshi ISI agents and HUJI agents. They have made them their voters and because of their votes they are winning elections for the last 30 years.

Sir, the hon. Minister, Shri Kapil said as to why should there be a confession. Why confession made in front of the police should be accepted as an evidence? What does he mean by that? Does he mean that the terrorists will come and given evidence against them? Will they confess it? If you just go on telling goody-goody words, will they confess what they have done? It is very natural that for confession, they will have to be put behind the bars. It is very natural. And the Government did the right thing by doing this. How can you say, why 180 days, why not 90 days and so on? It should have been more like three years. Don't we have value for our lives? They speak like this because West Bengal has not been attacked at any time and because Kerala has not been attacked. They speak as though other people do not have any value for their lives.

I will just come to my last point. We are going to have an institution called the National Investigation Agency. We are going to form the National Investigation Agency. It is a very good thing.

We are having an agency called the CBI. It is a highly respected agency in this country. Whenever there is some trouble, everybody says "Let the CBI investigate it". But when the UPA Government has come to power, to what level have they brought

it down? Take the case of Taj Corridor and the disproportionate assets case. I am not taking names. CBI said something when the Bahujan Samaj Party was with them and they wanted that the Taj Corridor case should not be investigated. Now, when another party has come to their support, that is, the Samajwadi Party, the CBI goes to court and says that the Government of India has asked them to go slow. They have entirely denigrated the prestige and integrity of CBI.

I have a very strong doubt that if this Government remains in power, they will behave in the same manner with this Agency also and they will denigrate the National Investigation Agency and they will make it the agent of the Government.

People of this country are listening to us and to them also. Let them decide who is for the nation, who is for the country, and who is for the people.

Thank you very much.

■



राज्यसभा

# आतंकवादियों के साथ क्रूरता दिखानी पड़ेगी

**कलराज मिश्र**

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 पर व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। सबसे प्रसन्नता की बात है कि आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए पूरा देश एक है, संसद एक है, संसद में जितने दल हैं, सब एक हैं और एकजुट होकर ऐसे कानून बनाएं, जिन कानूनों के माध्यम से आतंकवाद को, जो भी यहां कानूनी हिसाब से उसका निस्तारण करने में सहयोग प्राप्त होगा, उसको हम करेंगे, इस एक बड़ी अच्छी मानसिकता से प्रेरित होकर यह विधेयक आया है। इसमें यह बात भी कही गई थी कि इसी सत्र में या किसी सत्र में जब भी बिल लाते हैं, तो मान्यवर, आप जानते हैं कि उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है, लेकिन शासन ने, सरकार ने अपेक्षा की कि स्टैंडिग कमेटी में भेजे बगैर, क्योंकि यह सत्र छोटा है, इस विधेयक को पास कर देना चाहिए, इसको कानूनी स्वरूप प्रदान कर देना चाहिए। सबने बड़े सद्भाव से इसको लिया और उस सद्भाव के आधार पर इस विधेयक पर आज चर्चा हो रही है। ठीक है कि विधेयक की चर्चा के दौरान विभिन्न प्रकार के विचार लोगों के आएंगे, विचारों में मत-भिन्नता भी होगी और शायद समीक्षा करते समय किंचित् आलोचना भी हो सकती है, लेकिन उसको बड़ी सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए, क्योंकि सबकी मंशा एक है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, जिसके प्रति सबकी सहमति हो और वह कानून प्रभावी तौर पर लागू हो, ताकि आतंवादी घटनाओं को रोक सकने में हम सक्षम हो सकें। इसलिए यह जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभकरण विधेयक, 2008 यहां आया है, उसको जब तक कानूनी स्वरूप प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होगा और इसलिए उसको कानूनी स्वरूप

प्रदान करने के लिए, उसके प्रभाव को और प्रबलतर बनाने के लिए यह विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 लाया गया है। इसमें यह कहा गया है, जैसे उद्देश्यों और कारणों का कथन में इन्होंने साफ तौर पर कहा है-

''उसी रीति के बारे में, जिसमें आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों को लागू किया गया था, व्यक्त की गई चिंताओं और शिकायतों को, जिनके अन्तर्गत उसके दुरूपयोग के उदाहरण भी हैं, ध्यान में रखते हुए, अधिनियम को 2004 में निरस्ति कर दिया गया था। उसी समय, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक लड़ाई में अग्रणी रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373, तारीख 28 सितम्बर, 2001 के निबंधनों के अनुसार आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में कोई समझौता न करने की अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को ध्यान में रखते हुए विविविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में आतंकवाद और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने हेतु उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया था।

तब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगतियां हुई हैं। भारत के विभिन्न भागों में और अन्यत्र सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी घटनाएं और क्रियाकलाप चिंता बढ़ाते रहे हैं अत: ऐसे क्रियाकलापों से, जिसके अंतर्गत आतंकवाद का वित्तपोषण करने से संबंधित साधन भी हैं, निपटने के लिए विधित ढांचे का और पुर्विलोकन किया गया है''। प्रशासनिक सुधार आयोग का भी इन्होंने रेफरेंस दिया है। ''प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट' आतंकवाद का सामना करना धर्मपरायणता द्वारा संरक्षण करना' में इस संबंध में अनेक सिफारिशें भी की हैं। इस संबंध में विभिन्न अन्य स्रोतों से भी सुझााव प्राप्त हुए हैं।'' ये उद्देश्य के अंतर्गत है और उन्होंने यह मंशा जाहिर की है कि प्रभावी कानून बनना चाहिए। लेकिन जो 2001 का उल्लेख किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर को 1373 संकल्प लिए और उसमें उन्होंने महसूस किया कि सारे देश को आज जो आतंकवाद का खतरा पैदा हुआ है, सामान्य आपराधिक कानून के माध्यम से उस खतरे से हम निपट सकते हैं इसलिए कोई स्पेशल कानून बनाना चाहिए, एक ऐसा विशेष बनना चाहिए जिससे हम आतंकवाद का डटकर विरोध कर सकें। इसके लिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस संकल्प के माध्यम से



यह निर्देशित किया। जब 2001 में निर्देशित किया तो उस समय की सरकार ने एक कानून बनाया, पोटा कानून बनाया और पोटा कानून बनाने के बाद यह अपेक्षा की थी कि यह प्रभावी कानून है और इस प्रभावी कानून के माध्यम से आतंकवाद को हम किंचित रोकने की दिशा में प्रयत्नशील होंगे। प्रारम्भ में कई वक्ताओं ने कहा, हमारे बहुत से विद्वान मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किए और यह बात सही भी है कि आतंकवाद कानून से रूक जाता- ऐसा नहीं है क्योंकि जिस आतंकवाद का हम सामना कर रहे हैं वह आतंकवाद कहीं न कहीं से सुनियोजित तौर पर हमार यहां प्राक्सी वार के रूप में काम कर रहा है। आतंकवाद लड़ाई का एक माध्यम है और उसे हम प्राक्सी वार के रूप में देखते हैं। सबने यह स्वीकार किया है, पूरे सदन ने यह स्वीकार किया है, सत्ता पक्ष से हमार गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने, सबने इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान किसी न किसी रूप में आतंकवाद के माध्यम से हमारे ऊपर हमला कर रह है। जब हमला कर रहा है तो उसका स्वरूप कैसा था? पहले तो उसका स्वरूप ऐसा था कि बगैर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति दिखाकर जब वह हमला करता तो विस्फोट के माध्यम से हमला करता था, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर हमला करताथा, तत्काल लोग पकड़ में नहीं आते थे। फिर उसको लगा कि हम और आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं, जहां हमें हमला करना है, उस स्थान पर इतनी कमियां दिखाई पड़ रही हैं कि उन कमियों का हम लाभ उठा सकते हैं। उसी का यह परिणाम हुआ कि 26 नवम्बर को समुद्री माध्यम से हमला किया गया, हमारी सारी गुप्तचर एजेंसियों को ठेंगा दिखाकर, कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारी सारी समुद्री और तटीय सुरक्षा व्यवस्था विफल हो गयी, हमारा मुम्बई का सारा स्थानीय पुलिस प्रशासन- चाहे वह गुप्तचर विभाग रहा हो, चाहे पुलिस प्रशासन रहा हो- विफल हो गया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कई महीनों से उनकी योजना चल रही थी और वे सफल हो गए। जब सफल हो गए तो यह पूरे दो के लिए चुनौती थी। इसमें पार्टी और राजनीति का प्रश्न खड़ा नहीं होता है, इसमें किसी मजहब का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। हमारे देश में सभी मजहबों के लोग रहते हैं, हमारे देश में सभी पार्टियां हैं, परस्पर विरोधी विचारों की पार्टियां हैं लेकिन इस मामले पर सबने यह महसूस किया कि यह हमारे लिए चुनौती है। जब सबने महसूस किया

कि यह हमारे लिए चुनौती है तो सबने डटकर कहा कि इसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि इस परिस्थिति का आकलन करके लोगों को लगा, सत्तारूढ़ दल को लगा– हम विरोधी दल में हैं– विरोधी दल को लगा, सबको लगा।

तब एक साथ जुटकर इसका मुकाबला करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसने प्रेरित किया यह कानून बनाने के लिए, सही बात तो यह थी। पोटा आपने निरस्त कर दिया, चलिए, हम मान गए, आप सत्ता में आ गए, उसको निरस्त कर दिया। हम उसके बारे मे नही कहेंगे कि वह बहुत अच्छा था या आपका बहुत खराब है

ऐसा हम इस पर कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, नहीं तो सिब्बल साहब उठ करके अपना कुछ दिखाना शुरू कर देंगे। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने उसको निरस्त कर दिया और उसको निरस्त कर देने के बाद आपका जो स्टेटमेंट आया, मै। उसको दिखाना नहीं चाहता हूं लेकिन मैंने पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को भी स्टेटमेंट आया, और भी कई लोगों के स्टेटमेंट आए कि जो अपराध के विरूद्ध विद्यमान कानून है, सामान्य कानून है, इसमें ही काफी ताकत है, जो आतंकवाद का मुकाबला कर सकती है। इसी के माध्यम से हम इसको रोक सकते हैं। तथा इसमें पोटा जैसे कानून की जरूरत नहीं है। यह परिणाम इस तरह का इसने पैदा किया जिसने आम आतंकवादी के मनोबल को इसने बढ़ाया, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे परोक्ष रूप से हो। इससे उनको प्रोत्साहन मिला। इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। यदि इसको ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते हैं तो अपनी चेतना से, अपने चैतन्य से विश्वासघात करते हैं। मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इसको स्वीकार करना चाहिए कि इसके कारण ही आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने यह भी देखा कि इससे पहले लोगों ने कुछ चीजें तय की थीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ चीजें एप्रूव की थीं और प्रधान मंत्री जी से पूछा भी गया था कि क्या फेडरल एजेंसी बनेगी। मुझे पता है कि 2004 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बनाएंगे। लेकिन नहीं बनी। मेरे पास गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया आंकड़ा है, इस बीच में इतने जबर्दस्त तरीके से पूरे देश के अंदर आतंकवाद का प्रकोप बढ़ता गया, स्थानीय आधार पर लोगों को साथ लेकर उन्होंने अपना



कर्म करना शुरू कर दिया। आंकड़ों के अनुसार 625 जिलों में 258 जिले किसी न किसी रूप में आतंकवाद की चपेट में है। आंकड़ा सरकार का है। इसमें 16 राज्यों के 192 जिले माओवादियों के कब्जे में हैं। अभी हमार सीताराम जी कह रहे थे कि लेफ्ट का नाम क्यों रखा है। ये माओवादी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, 16 राज्यों के 192 जिले माओवादियों के कब्जे में हैं, 20 जिले पाकिस्तान से संचालित मजहबी जेहाइ के कब्जे में हैं। मेरा यह कहना है कि जब इनको लगने लगा कि कहीं न कहीं से ढिलाई बरती जा रहीहै, कहीं ने कहीं से इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता जा रहा है, जिसके कारण हमार ऊपर प्रभावी शिकंजा लगना चाहिए, वह नहीं लग पाएगा। और इसलिए सत्र विस्तरित होते रहे। उसी का नतीजा हुआ कि मुम्बई की घटना हुई। मैं यह नहीं गिनाना चाहता कि कितनी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार इसका उल्लेख किया था। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि परोक्ष रूप से प्रोक्सी वार, प्रत्यक्ष रूप से सीधे हमला इसबात ने हमको प्रेरित किया यह कानून बनाने के लिए और इस कानून के माध्यम से यह कोई रूक जाएगा, यही मान कर चलें, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। इसमें निश्चित रूप से हमें विचार करने की आवश्यकता है कि जो भी हमारा कानून बन रहा है जिसमें बहुत से लोगों ने तथा येचुरी जी ने भी कई देशों का उदाहरण दिया कि इतने लोग जेल में पड़े हुए हैं। कई लोगों ने कहा कि पोटा का दुरूपयोग हुआ। मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय चिदम्बरम जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप ही ने 1985 में टाडा पेश किया था और टाडा इसलिए लाया गया था कि उस समय पंजाब में आतंकवाद का प्रकोप था। उसको संदर्भित करते हुए टाडा कानून लाया गया था। टाडा कानून में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया और आतंकवाद को परिभाषित करते हुए यह तय किया गया कि आतंकवाद के लिए अगर कानून बनाना है तो आतंकवाद जैसा कानून बनना चाहिए।

मैं इस शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं, ताकि आतंकवादी यह समझे कि यह इतना प्रबल कानून है, जिस प्रबल कानून के शिकंजे से वह बच नहीं सकता है। इसलिए टाडा की जो कड़ाई की गई और आजकल लोग चर्चा करते हैं कि इतने लोग रहे और लोगों को इतना कष्ट दिया गया, तो वह तो आतंकवाद को ध्यान में रखकर, उसके अनुरूप कानून बना था। यह

दुर्भाग्य है कि उसका दुरूपयोग हुआ है, नहीं तो वह प्रभावी होता। उसका दुरूपयोग, इसलिए वह भी गया, फिर बाद में पोटा कानून बना। वह पोटा कानून भी आतंकवाद को ध्यान में रखकर बना था, वह आतंकवादी दुश्मन को ध्यान में रखकर बना था। वह किसी individual अपराधी को ध्यान मं रखकर नहीं बना था। यदि वह किसी individual अपराधी को ध्यान में रखकर बनता, तो मैं आप सब लोगों का समर्थन करता। जिन्होंने कहा कि इतने दिन क्यों रखा जा रहा है, इतने दिन का क्यों समय दिया जा रहा है, 180 दिन का समय क्यों दिया जा रहा है, तब शायद मैं यह कहता कि यह गलत किया जा रहा है। लेकिन आतंकवादी को ध्यान में रखकर कानून बनाया जा रहा है और ऐसे आतंकवादी को ध्यान में रखकर कानून बन रहा है, जो आतंकवादी हमारे ऊपर proxy war के रूप में हमला कर रहा है। एक दुश्मन देश का व्यक्ति हमारे ऊपर आकर हमला कर रहा है और हमला करके हमें destanilise करना चाहता है। इसके लिए जितना कड़े से कड़ा दंड हो सकता है, उतना कड़े से कड़ा दंड देना हमारा कर्त्तव्य भी बनता है, और देश के हित के लिए बनता है, इसीलिए तो पोटा कानून बना था। पोटा कानून को यह कहकर इसलिए निरस्त किया गया कि यह तो बड़ा क्रूर कानून है। अरे! आतंकवादियों के साथ क्रूरता नहीं दिखाएंगे, तो और क्या दिखाएंगे। हमें उनके साथ क्रूरता दिखानी पड़ेगी। महोदय, हमारा पूरा समय है। मैं यह कहना चाहता था कि हम अगर यह ध्यान में रखकर चर्चा करेंगे, तो शायद मत भिन्नता बहुत कम होगी। अगर हम यह ध्यान में रखकर चर्चा करेंगे कि आतंकवादी, आतंकवादी है, उस आतंकवादी के लिए कानून बन रहा है। यदि आतंकवादी के लिए कानून बन रहा है, तो हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इसमें भी जो 90 दिन और फिर 180 दिन का किया गया है कि उसकी हिरासत में रखा जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि इसको करना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस पर किसी प्रकार की रियासत करने की जरूरत नहीं है। आपने जमानत के बारे में leniency बरती है, लेकिन पोटा में leniency नहीं थी। जब तक उसका अपराध खत्म नहीं होता है, जब तक अधिकारी नहीं कह देता है, तब तक जमानत नहीं दी जाएगी, यह बात कही गई है। इसलिए उसको इस तरीके से लेने की जरूरत है और इसको उस ढंग से करने का प्रयत्न किया गया। मान्यवर, मैं यह कहना



चाहूंगा कि कानून उसी हिसाब से बनना चाहिए। जो फैडरल एजेंसी की बात कही है, यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की बात कही जा रही है, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले ही तय हो गया था कि फैडरल एजेंसी बननी चाहिए, लेकिन यह लेट बनी है। सभी गुप्तचर विभाग अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उसके लिए यह बात भी आई थी कि Group of ministerS ने जो पहले तय किया था कि एक मल्टी एजेंसी सैट-अप की जाए, उसकी सिफारिश करने की बात की थी। खुफिया ब्यूरो के तहत एजेंसियां बनाई गई थीं। पहली मल्टी एजेंसी रवपदज जों force intelligence गई थी, लेकिन इसको स्टाफ न देने के कारण, यह कार्यान्वित नहीं हो पाई इसका यह परिणाम हुआ कि हमें यह सारी दुर्दशा देखनी पड़ी, यह नहीं किया गया था। जब तक इसमें सामंजस्य स्थापित करते हुए काम नही किया जाएगा, तब तक नहीं होगा। कानून के तहत जो लोग गिरफ्तार होंगे, उसका त्वरित रूप से निस्तारण हो सके, इसके लिए जो अभी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बनाया गया है और जिसमें संविधान की पहली सूची का हवाला देकर यह बात आ रही है कि राज्यों से पूछा नहीं गया है, यह बात सही है कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार अपने हिसाब से काम कर सकती है और सामान्य तौर पर पहली सूची के अंतर्गत राज्यों को अपनी कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूरी स्वायत्तता है। लेकिन जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है, केन्द्रीय सरकार, सैन्ट्रल गवर्नमेंट उसके अनुरूप निर्णय ले सकती है। लेकिन व्यवहारिकता का तकाजा था सभी राज्यों से अगर एक बार वार्ता हो गई होती, तो ज्यादा अच्छा होता।

एक मिनट, उसके अनुसार सारी चीजें हो सकती थीं। अभी यह बात कही जा रही है, लेकिन मैं गृहमंत्री जी से इतना जरूर चाहूंगा कि सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं, रॉ है, आई.बी. है, डी.आई.ए. है, ये सभी एजेंसीज स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। आई.बी. के चीफ मि. गिरीश सक्सेना की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हमने अपनी जो सिफारिशें दी थी, उनके विचाराधीन लागू नहीं किया गया। उन्होंने सिफारिश में कहा था कि हमें आई.बी. में कम से कम तीस हजार फील्ड में ड्यूटी करने वाले आदमी चाहिए, कांस्टेबल चाहिए, लेकिन पूरा स्टाफ ट्वेन्टी फाइव थाउजेंड का है।

केवल तीन हजार पांच सौ लोग फील्ड में काम करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरीके से उन्हें और सुसज्जित करने की जरूरत है। आधुनिकतम हथियारों और बाकी सारी चीजों से उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। पुलिस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर इसे ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से हम जितना कार्य करना चाहते हैं, उतना कर सकेंगे। सब करने के बाद एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि कानून बनते हैं, लेकिन कानून का समुचित तौर पर क्रियान्वयन नहीं होता, इम्प्लिमेंटेशन नहीं होता है। उसे कैसे इम्पिलमेंट कराया जाए, यदि इस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कपिल सिब्बल जी ने कई प्रकार की बातें कहीं, वे केवल उत्तर प्रत्युत्तर में रह गए थे, मैं उनसे और आपके माध्यम से गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि मिसयूज तो चीजों का होता है, इसका भी मिसयूज होता, इसका मिसयूज न होने पाए, इसकी चिंता करें। चीजों को क्रियान्वित करने का प्रभावी तौर पर कार्य करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि जिस मंशा के आधार पर यह कानून बनाया जा रहा है, वह कानून सफलीभूत होगा और आगे चलकर इस कानून का प्रयोग करके आए हुए आतंकवादियों को जो पकड़ा जाएगा, हम उनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकेंगे।

■